यूपी की
उड़ान

बजट 2022-23

योगी सरकार ने पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली व परिवहन पर विशेष जोर दिया है

इन्फ्रॉस्ट्रक्चर • सुरक्षा • पर्यटन • बिजली

10,00,000 करोड़ रुपये का निवेश दस वर्षों में लाने के लिए योगी सरकार ने बजट के माध्यम से खींचा खाका

22.50 करोड़ से कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना से लगेंगी स्ट्रीट लाइटें

1,444 करोड़ कानपुर, गोरखपुर, आगरा और वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए

1,306 करोड़ दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम रेल के लिए प्रस्तावित

योगी सरकार ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे करने पर जोर दिया है। सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए बजट में रोडमैप तैयार किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में और सुविधाएं बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा भी दिया है।

निवेश के लिए योगी सरकार का रोडमैप तैयार

गंगा एक्सप्रेसवे, अटल इंडस्ट्रियल मिशन, गति शक्ति योजना और ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए बजट में किया प्रावधान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अगले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के लिए अपना रोडमैप बजट के माध्यम से पेश किया है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबे छह लेन गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण लिए 695.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस मिशन की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में की गई थी।

औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत कनेक्टिविटी सुविधाओं पर 897 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क (ओएफसी) के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ मिलेंगे। संकल्प बजट में बताए गए सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

300 करोड़ ओएफसी के लिए

18,561 करोड़ सड़कों व पुलों के निर्माण पर होंगे खर्च

1,965 करोड़ से गांव व बसावटों को सर्वऋतु संपर्क मार्गों से जोड़ेंगे

269 करोड़ पिछली बार से ज्यादा मेट्रो रेल विस्तार को मिले

82 करोड़ वाराणसी में रोपवे सुविधा के लिए प्रस्तावित

कृषि उपज की बिक्री की सुविधा को ध्यान में रखकर बनेंगी सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचवर्षीय अनुरक्षा के बाद नवीनीकरण के लिए 63.15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य राजमार्गों के नए कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ का बजट है। कृषि उपज की बिक्री की सुविधा के तहत सड़कें बनाने पर 100 करोड़ दिए जाएंगे। नाबार्ड की मदद से आरआईडीएफ योजना के तहत ग्रामीण मार्गों व लघु सेतुओं के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के कंप्यूटराइजेशन के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

बनेंगी नई सड़कें, पुरानी होंगी दुरुस्त

लखनऊ। सरकार ने सड़कों व पुलों को प्राथमिकता पर रखा है। पीडब्ल्यूडी के लिए 31,658 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें नई सड़कों व पुलों के निर्माण के साथ पुराने कार्यों की दशा सुधारने पर जोर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले विभाग को 2204 करोड़ ज्यादा मिला है। 2021-22 में पीडब्ल्यूडी के लिए 29,454 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 2022-23 के बजट में सड़कों व सेतुओं के निर्माण के लिए 18,561 करोड़ का प्रावधान है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड की योजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये मिलेंगे।

पीडब्ल्यूडी

2,204 करोड़ रुपये का बजट में इजाफा

शहरों में जाम से निपटने के लिए बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में राजघाट पुल से रामनगर तक स्टेनलेस मॉडल सड़क के लिए 500 करोड़ दिए जाएंगे। रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1250 करोड़ और प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के लिए 2600 करोड़ दिए गए हैं। स्टेट हाईवे के लिए 1600 करोड़ का प्रावधान है। राज्य सड़क निधि में स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में 3750 करोड़ देगी। ब्यूरो

201 करोड़ अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए

अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर और अयोध्या एयरपोर्ट से हवाई सेवा आने वाले दिनों में शुरू होगी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को पूरा करने के लिए 201 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई से परहेज, पुरानी योजनाओं पर ही फोकस

लखनऊ। सरकार ने पिछले साल की तरह इस बजट में भी शहरवासियों को शुद्ध पेयजल, गरीबों को सस्ते मकान व शौचालय देने पर फोकस किया है। स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित 10 शहरों में परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर नई घोषणा से परहेज करते हुए सरकार ने पहले से चल रही योजनाओं पर ही फोकस किया। इसके लिए इस बजट में भी 1353.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने केंद्रीय मदद से चलने वाली स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और अमृत योजना के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा

नगर विकास

2000 करोड़

स्मार्ट सिटी वाले शहर लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद व सहारनपुर के प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति को तेज करने के लिए। पिछले साल भी इतना ही राशि की व्यवस्था की गई थी।

200 करोड़ आदर्श नगर पंचायतों के लिए दिए गए

पिछले साल शुरू की गई 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत' और 'मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना' को ही आगे बढ़ाया है। ब्यूरो

1,354 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन के लिए

2,000 करोड़ अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तावित

2,200 करोड़ पूर्व से चल रही अमृत योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए

16,000 लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से दिया जाएगा रोजगार

112.50 करोड़ प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए किए प्रस्तावित

प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ व महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

झलकारी बाई हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

35 करोड़ रुपये अयोध्या में सीपेट केंद्र निर्माण व संयंत्र खरीद के लिए

250 करोड़ पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली मुहैया कराने के लिए खर्च किए जाएंगे।

10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के अंतर्गत पावरलूम व हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर देने के लिए

215 करोड़ मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना के लिए व्यवस्था की गई

457 करोड़ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों का होगा विकास

विंध्यधाम व चित्रकूट धाम के विकास के लिए 7 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अयोध्या और वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए 100-100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बिजली पर पिछली बार से 27.15% ज्यादा होगा खर्च

- रिवैम्पड स्कीम से सुधरेगी बिजली व्यवस्था
- 47,900 करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र का बजट

लखनऊ। प्रदेश में बिजली सुधार के लिए केंद्र के सहयोग से 31 हजार करोड़ रुपये की संशोधित वितरण योजना (रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम) शुरू की जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने अंशपूंजी के रूप में 5530 करोड़ की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत लाइन हानियां कम करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इस योजना को तीन वर्ष में पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिजलीघरों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक अनवरत आपूर्ति के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह नई योजनाओं के लिए 10,575.44 करोड़ और सरकारी विभागों के बकाया बिलों के भुगतान के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 3500 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी बॉन्ड पर देय ब्याज की अंशपूंजी 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो

1000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों को शाम 7 से सुबह 6 बजे तक आपूर्ति के लिए

सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था पर जोर

सेफ सिटी परियोजना और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान, बनेगी महिला बटालियन

लखनऊ। बजट में कानून-व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। सेफ सिटी परियोजना व महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। वहीं, चालू योजनाओं को रफ्तार देने के लिए 7100 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है। सरकार ने उप्र विशेष सुरक्षा बल के गठन के लिए 276.66 करोड़ और यूपी 112 योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 730.88 करोड़ की व्यवस्था की है। ब्यूरो

523.34 करोड़ लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में सेफ सिटी योजना पर होंगे खर्च

लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला बटालियन

आतंकी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेरठ और बहराइच में प्रस्तावित कमांडो सेंटर के लिए 42 लाख रुपये की व्यवस्था की है। इसी तरह थानों में सुरक्षा उपकरणों व अस्त्र-शस्त्र पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला बटालियन के लिए 1703 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

1,700 करोड़ एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट

इकाई अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूटधाम, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज व सहारनपुर मंडल में की जाएगी स्थापना।

- सरकार ने 1965 करोड़ रुपये पुलिस विभाग के आवासीय, गैर आवासीय भवनों व पुलिस लाइन्स के लिए व्यवस्था की है।

सामाजिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को देंगे धार

लखनऊ। योगी सरकार ने महापुरुषों के जरिए सामाजिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने के लिए संत रविदास, कबीर दास जैसे महापुरुषों के नाम पर संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र बनाने के साथ अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक सड़क बनाने की योजना की है। सरकार धार्मिक स्थलों पर भव्य आयोजन भी करेगी। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र बनाने और संत कबीर दास संग्रहालय के लिए 25-25 करोड़ दिए हैं। इसी तरह 77 करोड़ रुपये वाराणसी में निर्मित गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचमार्ग के लिए प्रस्तावित है।

अयोध्या में जनसुविधाओं के विकास व पार्किंग के निर्माण के लिए 209.70 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। ब्यूरो

300 करोड़ राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक संपर्क मार्ग को दिए

कल्याणकारी राज्य की दिशा में सफल प्रयास

एक्सपर्ट कमेंट

बजट को राजनीतिक नजरिए से देखने के बजाय आर्थिक पहलू से समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन ज्यादा उचित होगा। संविधान निर्माण के समय आर्थिक अभाव में शिक्षा व स्वास्थ्य के मूलभूत अधिकारों को भविष्य में राज्य का उत्तरदायित्व बताते हुए नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में रखा गया था। सरकार ने बजट में इस ओर सधे कदम बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। श्रमिकों और पेशे वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 300 करोड़ का बजट आवंटन सराहनीय कदम है।

स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ गरीबों को मिल सके इसके लिए आयुष्मान भारत के तहत 500 करोड़ और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 250 करोड़ की व्यवस्था करने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। किसानों को समृद्ध बनाने के दो तरीके हैं। पहला फसल की लागत घटा दी जाए या उपज के दाम बढ़ा दिए जाएं। लागत घटाने के लिए सरकार ने नलकूप, लघु डाले आदि के लिए 18 हजार करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली तथा सोलर पंप की व्यवस्था की है।

प्रदेश की सड़कों में सुधार के लिए अभी काफी गुंजाइश है। इसके लिए आवंटित 18500 करोड़ का बजट उपलब्ध संसाधनों की सीमा में भले ही तर्कसंगत हो, लेकिन कम है।

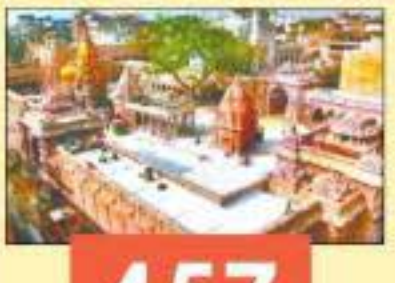

गोपाल अग्रवाल
व्यापारी नेता

बिगड़ी अर्थव्यवस्था में आएगा सुधार

बजट में कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं समेत अन्य क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिवेश की बढ़ोतरी, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस पर खास ध्यान दिया गया है। दावा किया गया है कि यह बजट गत वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत से ज्यादा है। लेकिन इसमें मुद्रास्फीति भी शामिल है जो छह प्रतिशत तक रहती है। ऐसे में शुद्ध रूप से यह बजट एक से दो प्रतिशत ही ज्यादा होगा। कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, उसमें सुधार लाने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह बजट कम है।

कृषि क्षेत्र के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनमें खर्च का आवंटन, लघु सिंचाई, सौर ऊर्जा, बाढ़ नियंत्रण, खाद उर्वरक के वितरण, बीज वितरण पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र में भी और बजट की जरूरत है। गन्ना किसानों के लिए पांच नई मिलें खोलने की बात कही गई है। इसमें भी कुछ और बजट चाहिए।

प्रो. नीलमणि प्रसाद वर्मा
अर्थशास्त्र विभाग व पूर्व डीन, बीबीएयू